Gyanvividha, Vol.-3; Issue-1 (Jan.-March) 2026 : PP-235-243

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-4.5
Vol.-3; Issue-1 (Jan.-March) 2026
Page No.- 235-243
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

Dr. Sandeep Kumar

Department of History, Jay Prakash University Chapra (Bihar).
Orchid I'd : 0009-0006-9983-4663

Corresponding Author :

Dr. Sandeep Kumar

Department of History, Jay Prakash University Chapra (Bihar).
Orchid I'd : 0009-0006-9983-4663

हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय : एक ऐतिहासिक विश्लेषण

सारांश : यह शोध पत्र 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय की जटिल प्रक्रिया का एक गहन ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद जहाँ अधिकांश रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गईं, वहीं हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में बने रहने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी।

प्रस्तुत शोध में उन राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की जांच की गई है जिन्होंने इस गतिरोध को जन्म दिया, जिसमें 'यथास्थिति समझौता' (Standstill Agreement) और उसकी विफलता मुख्य रही। साथ ही, यह पत्र रजाकारों के सांप्रदायिक दमन और उसके जवाब में शुरु हुए तेलंगाना किसान आंदोलन के प्रभाव को भी रेखांकित करता है। अंततः, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ संकल्प और 'ऑपरेशन पोलो' (13-17 सितंबर 1948) नामक सैन्य कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद के सफल एकीकरण का सविस्तार वर्णन किया गया है।

निष्कर्षतः, यह शोध स्पष्ट करता है कि हैदराबाद का विलय न केवल भारत की भौगोलिक अखंडता के लिए अनिवार्य था, बल्कि इसने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की नींव को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य शब्द : हैदराबाद रियासत, निजाम, सरदार पटेल, ऑपरेशन पोलो, रजाकार, भारतीय संघ, ऐतिहासिक विलय।

प्रस्तावना : 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही न केवल ब्रिटिश भारत स्वतंत्र हुआ, बल्कि 560 से अधिक देसी रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोपरिता (Paramountcy) भी समाप्त हो गई (**Menon, 1956**)। तकनीकी रुप से ये रियासतें संप्रभु बन गईं और उनके पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल

और रियासती विभाग के सचिव वी.पी. मेनन के सामने इन बिखरी हुई कड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत के निर्माण की विशाल चुनौती थी (**Copland, 1997**)। जहाँ अधिकांश रियासतों ने अपनी भौगोलिक स्थिति और जनता की इच्छा को देखते हुए स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया, वहीं जूनागढ़, कश्मीर और विशेष रूप से हैदराबाद ने एक गंभीर संवैधानिक और सुरक्षा संकट पैदा कर दिया (**Guha, 2007**)।

हैदराबाद का महत्व: भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य : हैदराबाद रियासत भारत के हृदय स्थल (दक्कन के पठार) में स्थित थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 82,000 वर्ग मील था—जो उस समय के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा था (**Munshi, 1957**)। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती थी, क्योंकि यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले सभी प्रमुख संचार और परिवहन मार्गों के केंद्र में स्थित था।

आर्थिक रूप से, हैदराबाद भारत की सबसे धनी रियासत थी। इसकी अपनी मुद्रा (ओसमानिया सिक्का), अपनी रेलवे प्रणाली और एक उन्नत डाक व्यवस्था थी (**Smith, 1950**)। सांस्कृतिक रूप से, हैदराबाद गंगा-जमुनी तहजीब का केंद्र था, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या (लगभग 85%) और अल्पसंख्यक मुस्लिम शासक वर्ग के बीच सदियों से एक अनूठा समन्वय विद्यमान था। हालांकि, यह संतुलन 20वीं सदी के मध्य में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण डगमगाने लगा था (**Sherwani, 1986**)।

समस्या का कथन: निजाम मीर उस्मान अली खान की स्वतंत्र महत्वाकांक्षा : समस्या का मुख्य केंद्र सातवें निजाम, मीर उस्मान अली खान की वह जिद थी, जिसमें वे हैदराबाद को एक "स्वतंत्र इस्लामी संप्रभु राज्य" के रूप में बनाए रखना चाहते थे (**Zubrzycki, 2006**)। निजाम का तर्क था कि चूंकि हैदराबाद ने कभी भी ब्रिटिश शासन के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया था, इसलिए वह एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने का हकदार है।

निजाम की इस महत्वाकांक्षा को 'इत्तेहाद-उल-मुसलमीन' जैसे संगठनों और कासिम रिज़वी के 'रजाकारों' (अर्धसैनिक बल) से खाद-पानी मिला (**Benichou, 2000**)। रजाकारों के बढ़ते प्रभाव ने रियासत के भीतर एक हिंसक और सांप्रदायिक माहौल पैदा कर दिया, जिससे बहुसंख्यक आबादी में असुरक्षा की भावना पैदा हुई। भारत सरकार के लिए एक "स्वतंत्र हैदराबाद" न केवल भौगोलिक अखंडता के लिए खतरा था, बल्कि यह देश के भीतर एक 'दूसरे पाकिस्तान' के उभरने जैसा था, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर सकता था (**Talbot & Singh, 2009**)। यही वह बिंदु था जहाँ कूटनीति विफल होने लगी और अनिवार्य हस्तक्षेप की नींव पड़ी।

विलय की चुनौतियाँ : हैदराबाद का भारत में विलय कोई सरल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह कूटनीतिक छल, आंतरिक विद्रोह और चरमपंथी हिंसा का एक जटिल मिश्रण था।

यथास्थिति समझौता: एक कूटनीतिक ढाल : अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो निजाम ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार और हैदराबाद के बीच एक 'यथास्थिति समझौता' हुआ (**Menon, 1956**)। इस समझौते का उद्देश्य एक वर्ष का समय देना था ताकि शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके।

हालांकि, निजाम ने इस समय का उपयोग भारत के साथ जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने और विदेशी राष्ट्रों (विशेषकर पाकिस्तान और ब्रिटेन) से समर्थन प्राप्त करने के लिए किया (**Copland, 1997**)। भारत सरकार ने आरोप लगाया कि निजाम ने गुप्त रूप से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये का ऋण दिया और अपनी सेना का विस्तार करके समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया (**Munshi, 1957**)।

रजाकारों का उदय और कासिम रिज़वी की भूमिका : इस कालखंड की सबसे भयावह चुनौती 'मजलिस-ए-

इत्तेहादुल मुसलमीन' (MIM) और उसके उग्रवादी विंग 'रजाकारों' का उदय था। कासिम रिज़वी के नेतृत्व में रजाकारों ने घोषणा की कि हैदराबाद एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य रहेगा और उन्होंने "लाल किले पर निजाम का झंडा फहराने" जैसे भड़काऊ नारे दिए (**Benichou, 2000**)।

रजाकारों ने रियासत के भीतर रहने वाली हिंदू बहुसंख्यक आबादी और विलय के समर्थकों पर भीषण अत्याचार शुरु कर दिए। हत्या, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं ने रियासत में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। **लुसिएन बेनिचू (2000)** के अनुसार, रजाकारों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि निजाम स्वयं उनके हाथों की कठपुतली बन गए थे।

आंतरिक विद्रोह: तेलंगाना किसान आंदोलन : जहाँ एक ओर रजाकार आतंक फैला रहे थे, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्टों के नेतृत्व में तेलंगाना किसान आंदोलन ने निजाम के शासन की जड़ों को हिला दिया था (**Sundarayya, 1972**)। यह आंदोलन मुख्य रूप से दमनकारी जमींदारी प्रथा (देशमुख और जागीरदार) के खिलाफ था, लेकिन इसने निजाम के प्रशासनिक नियंत्रण को पूरी तरह विफल कर दिया। रियासत अब तीन तरफ से दबाव में थी: भारत सरकार, रजाकारों की हिंसा और आंतरिक कृषक विद्रोह।

हैदराबाद रियासत: शक्ति संरचना और त्रिकोणीय संघर्ष : 1947-48 के दौरान हैदराबाद एक बहु-आयामी संघर्ष का केंद्र बन गया था। इसे समझने के लिए हम शक्ति के मुख्य केंद्रों और उनके उद्देश्यों का विश्लेषण निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं:

शक्ति संघर्ष का विस्तृत विश्लेषण (Table of Conflict)

शक्ति केंद्र	मुख्य नेतृत्व	प्राथमिक उद्देश्य	कार्यप्रणाली और प्रभाव
निजाम प्रशासन	मीर उस्मान अली खान	हैदराबाद की संप्रभुता और 'आजाद हैदराबाद' का अस्तित्व बचाना।	कूटनीतिक देरी करना, पाकिस्तान से गुप्त सैन्य मदद लेना और यथास्थिति समझौते का सहारा लेना (Munshi, 1957)।
चरमपंथी (रजाकार)	कासिम रिज़वी	हैदराबाद में मुस्लिम वर्चस्व बनाए रखना और भारत में विलय का हिंसक विरोध।	रजाकारों के माध्यम से नागरिक आबादी पर आतंक, सांप्रदायिक हिंसा और निजाम को कट्टरपंथी फैसलों के लिए मजबूर करना (Noorani, 2014)।
भारत सरकार	सरदार वल्लभभाई पटेल एवं वी.पी. मेनन	भारत की भौगोलिक अखंडता सुनिश्चित करना और रियासत का पूर्ण विलय।	'गाजर और छड़ी' की नीति। पहले कूटनीतिक दबाव, फिर आर्थिक घेराबंदी और अंततः सैन्य हस्तक्षेप (Menon, 1956)।
लोकतांत्रिक बल (स्टेट कांग्रेस)	स्वामी रामानंद तीर्थ	उत्तरदायी सरकार की स्थापना और भारत में संवैधानिक विलय।	सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन और जन-जागरूकता अभियान।
सशस्त्र विद्रोही (कम्युनिस्ट)	पुचपल्ली सुंदरैया एवं अन्य	दमनकारी जमींदारी प्रथा का अंत और निजाम के शासन को उखाड़ फेंकना।	तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह, 'ग्राम राज्य' की स्थापना और रजाकारों का मुकाबला (Sundarayya, 1972)।

ऐतिहासिक संदर्भ और विश्लेषण : इस शक्ति संरचना में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब निजाम अपने ही द्वारा पोषित रजाकारों के प्रभाव में पूरी तरह आ गए। **के.एम. मुंशी (1957)** के अनुसार, निजाम प्रशासन एक समय पर इतना पंगु हो गया था कि राज्य की वास्तविक सत्ता कासिम रिज़वी के हाथों में चली गई थी।

दूसरी ओर, भारत सरकार के लिए यह केवल एक रियासत का मामला नहीं था। सरदार पटेल का मानना था कि हैदराबाद भारत के नक्शे पर एक "कैंसर" की तरह है, जिसे यदि समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो यह पूरे देश के स्वास्थ्य (एकता) को बिगाड़ देगा (**Guha, 2007**)।

भारत सरकार का दृष्टिकोण : नीतिगत आधार और कूटनीतिक प्रयास : हैदराबाद के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण केवल एक रियासत के विलय का मामला नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता की पहली बड़ी परीक्षा थी।

सरदार पटेल की 'लौह' नीति: "भारत के पेट में कैंसर" : भारत के तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री और रियासती विभाग के प्रमुख सरदार वल्लभभाई पटेल का मानना था कि भारत के मध्य में एक स्वतंत्र और संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण राष्ट्र का अस्तित्व बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने हैदराबाद की स्थिति की तुलना "शरीर के भीतर एक कैंसर" से की थी, जिसका समय पर उपचार (विलय) न होने पर पूरा शरीर (भारत) संक्रमित हो सकता था (**Menon, 1956**)।

पटेल का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट था:

1. **भौगोलिक अखंडता:** हैदराबाद का स्वतंत्र रहना उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क को पूरी तरह काट सकता था।
2. **सांप्रदायिक शांति:** रजाकारों की हिंसा पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की क्षमता रखती थी।
3. **लोकतंत्र:** 85% हिंदू आबादी पर एक निरंकुश अल्पसंख्यक शासन का बने रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध था (**Guha, 2007**)।

कूटनीतिक वार्ता और वी.पी. मेनन की भूमिका : रियासती विभाग के सचिव वी.पी. मेनन ने बार-बार निजाम और उनके प्रतिनिधियों (जैसे सर सुल्तान अहमद और नवाब छतरी) के साथ बातचीत की। भारत सरकार ने अत्यधिक लचीलापन दिखाते हुए हैदराबाद को अन्य रियासतों की तुलना में अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव भी रखा, बशर्ते वह रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषयों पर भारत के साथ जुड़े (**Copland, 1997**)।

कूटनीतिक विकल्पों का विश्लेषण (चार्ट) : भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही से पहले किन चरणों का पालन किया, उसे नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है:

चरण (Phase)	रणनीति (Strategy)	उद्देश्य (Objective)	परिणाम (Result)
प्रथम चरण	अनुनय	स्वेच्छा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना।	निजाम द्वारा अस्वीकार।
द्वितीय चरण	यथास्थिति समझौता	एक वर्ष का समय देकर शांतिपूर्ण हल खोजना।	निजाम द्वारा समझौते का उल्लंघन और सैन्य विस्तार।
तृतीय चरण	आर्थिक प्रतिबंध	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोककर दबाव बनाना।	निजाम का पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र की ओर रुख।
अंतिम चरण	हस्तक्षेप	'ऑपरेशन पोलो' के माध्यम से सैन्य समाधान।	हैदराबाद का पूर्ण विलय।

माउंटबेटन का प्रभाव और 'छड़ी' बनाम 'गाजर' : लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, अंतिम समय तक एक शांतिपूर्ण समझौते (जैसे 'माउंटबेटन प्रस्ताव') के पक्षधर थे। उन्होंने निजाम को समझाने की कोशिश की कि भारत के साथ न जुड़ना उनके और उनके राजवंश के लिए आत्मघाती होगा (**Zubrzycki, 2006**)। हालांकि, कासिम रिज़वी के दबाव में निजाम ने हर कूटनीतिक 'गाजर' को ठुकरा दिया, जिससे अंततः भारत को 'छड़ी' (सैन्य बल) का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

भारत सरकार का दृष्टिकोण: कूटनीतिक विफलता के कारण और सैन्य निर्णय : अगस्त 1948 तक आते-आते यह स्पष्ट हो गया था कि बातचीत की मेज पर समाधान की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। कूटनीतिक विफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

निजाम का अंतरराष्ट्रीयकरण का प्रयास : निजाम ने भारत के साथ आंतरिक मामला सुलझाने के बजाय इसे संयुक्त राष्ट्र (UN) में ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने दलील दी कि हैदराबाद एक स्वतंत्र देश है और भारत उस पर अवैध दबाव डाल रहा है (**Noorani, 2014**)। भारत सरकार के लिए यह संप्रभुता को सीधी चुनौती थी, क्योंकि पटेल का मानना था कि यह भारत का आंतरिक मामला है, न कि अंतरराष्ट्रीय विवाद।

पाकिस्तान का हस्तक्षेप और हथियारों की तस्करी : निजाम प्रशासन ने गुप्त रूप से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये का ऋण दिया और सिडनी कॉटन (Sydney Cotton) नामक एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के माध्यम से हथियारों की तस्करी शुरू कर दी (**Munshi, 1957**)। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा था। लॉर्ड माउंटबेटन के भारत छोड़ने (जून 1948) के बाद, समझौते की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वह भी खत्म हो गई।

रजाकारों का हिंसक चरम: 'दबाव बिंदु' (The Breaking Point) : कासिम रिज़वी के नेतृत्व में रजाकारों ने न केवल रियासत के भीतर बल्कि भारतीय सीमाओं (मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रांत) पर भी हमले शुरू कर दिए थे। ट्रेनों को रोका गया और यात्रियों के साथ लूटपाट की गई। **वी.पी. मेनन (1956)** के अनुसार, स्थिति ऐसी हो गई थी कि यदि भारत हस्तक्षेप नहीं करता, तो दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे।

निर्णय की प्रक्रिया (चार्ट: कूटनीति से युद्ध तक का सफर) : नीचे दिए गए चार्ट में उन प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है जिन्होंने नेहरू और पटेल को 'ऑपरेशन पोलो' की अनुमति देने पर विवश किया:

घटना (Event)	तिथि (Date)	प्रभाव (Impact)
लायेक अली का प्रधानमंत्री बनना	मार्च 1948	निजाम प्रशासन पर रजाकारों का पूर्ण नियंत्रण।
हथियारों की तस्करी का खुलासा	जून-जुलाई 1948	भारत द्वारा आर्थिक नाकेबंदी सख्त करना।
संयुक्त राष्ट्र को पत्र	अगस्त 1948	मामले को अंतरराष्ट्रीय बनाने की निजाम की कोशिश।
नान्देव और बीदर की हिंसा	सितंबर 1948	भारत सरकार द्वारा 'अंतिम अल्टीमेटम' जारी करना।
ऑपरेशन पोलो का आदेश	9 सितंबर 1948	सरदार पटेल द्वारा सेना को कूच करने का निर्देश।

सैन्य निर्णय: 'छड़ी' का अंतिम प्रयोग : जहाँ प्रधानमंत्री नेहरू अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और युद्ध की संभावनाओं को लेकर चिंतित थे, वहीं सरदार पटेल का रुख अडिग था। पटेल ने स्पष्ट किया कि "हवा में बातें करने का समय बीत

चुका है।" 9 सितंबर 1948 को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए सैन्य पुलिस कार्यवाही (Police Action) अनिवार्य है (**Pradhan, 2014**)। इसे 'पुलिस कार्यवाही' इसलिए कहा गया ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे दो देशों के बीच युद्ध के बजाय एक आंतरिक सुरक्षा अभियान माना जाए।

ऑपरेशन पोलो: सैन्य कार्यवाही (Operation Polo: Military Action) : जब कूटनीति के सभी मार्ग बंद हो गए, तो भारत सरकार ने **'ऑपरेशन पोलो'** का निर्णय लिया। इसे 'पुलिस कार्यवाही' इसलिए कहा गया क्योंकि भारत इसे दो देशों के बीच का युद्ध नहीं, बल्कि अपने ही एक हिस्से में कानून-व्यवस्था की बहाली का अभियान मानता था (Menon, 1956)।

सैन्य रणनीति और कमान : इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल ई.एन. गोडार्ड (Southern Command) ने किया, जबकि मैदान पर सैन्य संचालन की जिम्मेदारी मेजर जनरल जे.एन. चौधरी (1 Armoured Division) के कंधों पर थी। भारतीय सेना ने हैदराबाद को चारों ओर से घेरने की रणनीति बनाई।

पांच दिनों का घटनाक्रम (13-17 सितंबर 1948) :

- **प्रथम दिन (13 सितंबर):** भारतीय सेना ने दो मुख्य दिशाओं से प्रवेश किया—पश्चिम में **शोलापुर** से और पूर्व में बेजवाड़ा (विजयवाड़ा) से। 'हल्की' और 'कड़ी' रेजिमेंटों ने रजाकारों की अग्रिम चौकियों को तेजी से ध्वस्त कर दिया (**Pradhan, 2014**)।
- **द्वितीय दिन (14 सितंबर):** औरंगाबाद पर कब्जा कर लिया गया। रजाकारों ने कुछ स्थानों पर प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों और हवाई शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके।
- **तृतीय दिन (15 सितंबर):** जालना और निर्मल जैसे महत्वपूर्ण शहर भारतीय नियंत्रण में आ गए। निजाम की सेना और रजाकारों के बीच समन्वय पूरी तरह टूट चुका था।
- **चतुर्थ दिन (16 सितंबर):** भारतीय सेना हैदराबाद शहर के मुहाने पर पहुँच गई। निजाम को अहसास हुआ कि पाकिस्तान से कोई मदद नहीं आने वाली है और न ही संयुक्त राष्ट्र तुरंत हस्तक्षेप करेगा (**Noorani, 2014**)।
- **अंतिम दिन (17 सितंबर):** शाम 5:00 बजे, निजाम की सेना के कमांडर मेजर जनरल एल. एड्रूस ने आत्मसमर्पण कर दिया। शाम को निजाम ने रेडियो पर आत्मसमर्पण की घोषणा की और अपनी पिछली नीतियों के लिए रजाकारों को जिम्मेदार ठहराया (**Munshi, 1957**)।

सैन्य शक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण

विशेषता	भारतीय सेना	हैदराबाद (निजाम) सेना + रजाकार
नेतृत्व	मेजर जनरल जे.एन. चौधरी	मेजर जनरल एल. एड्रूस और कासिम रिज़वी
सैन्य बल	लगभग 35,000 (बख्तरबंद डिवीजन के साथ)	22,000 नियमित सैनिक + 2,00,000 रजाकार (असंगठित)
हवाई शक्ति	टेम्पेस्ट और हरिकेन विमानों का समर्थन	नगण्य (केवल परिवहन हेतु कुछ विमान)
परिणाम	पूर्ण विजय और नियंत्रण	विनाशकारी हार और आत्मसमर्पण

आत्मसमर्पण और निजाम का पतन : 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल जे.एन. चौधरी ने हैदराबाद के सैन्य गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। निजाम मीर उस्मान अली खान, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब एक भारतीय राज्य के संवैधानिक प्रमुख (राजप्रमुख) की भूमिका तक सीमित रह गए (**Zubrzycki, 2006**)। इस

कार्यवाही ने भारत के मानचित्र से एक बड़ी अस्थिरता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।

विलय के बाद के परिणाम (Post-Integration Analysis) : 17 सितंबर 1948 को निज़ाम के आत्मसमर्पण के बाद, हैदराबाद में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस संक्रमण काल को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

सैन्य प्रशासन और व्यवस्था की बहाली (1948-1949) : विलय के तुरंत बाद, मेजर जनरल जे.एन. चौधरी को हैदराबाद का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया। उनका प्राथमिक कार्य रज़ाकारों के आतंक को समाप्त करना और सांप्रदायिक हिंसा को रोकना था (**Menon, 1956**)।

- **निशस्त्रीकरण:** रज़ाकारों के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके हथियारों को जब्त कर लिया गया।
- **प्रशासनिक शुद्धिकरण:** निज़ाम के दौर के उन अधिकारियों को हटाया गया जो अलगाववाद या रज़ाकारों के समर्थक थे।

सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट (Sunderlal Committee Report) : विलय के दौरान और उसके तुरंत बाद हुई हिंसा की जांच के लिए भारत सरकार ने पंडित सुंदरलाल, काज़ी अब्दुल गफ्फार और मौलाना अब्दुर मिस्री की एक समिति गठित की।

- इस समिति की रिपोर्ट (जो कई दशकों तक सार्वजनिक नहीं की गई) ने यह उजागर किया कि सैन्य कार्यवाही के दौरान कुछ क्षेत्रों में गंभीर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी (**Noorani, 2014**)। इसने सरकार को भविष्य में अधिक समावेशी नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया।

जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन : हैदराबाद में सदियों से चली आ रही दमनकारी जागीरदारी और देशमुख प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यह तेलंगाना के किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत थी।

- **भूमि सुधार:** निज़ाम की निजी संपत्ति (सरफ-ए-खास) को राज्य सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया और किसानों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू हुई (**Pavier, 1981**)।

लोकतांत्रिक संक्रमण (Transition to Democracy) :

1950 में, एम.के. वेल्लोडी (M. K. Vellodi) को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जो एक वरिष्ठ सिविल सेवक थे।

- **राजप्रमुख का पद:** निज़ाम मीर उस्मान अली खान को 'राजप्रमुख' बनाया गया, जिससे पुरानी व्यवस्था के समर्थकों में असंतोष कम हुआ।
- **प्रथम चुनाव:** 1952 के आम चुनावों के बाद, बी. रामकृष्ण राव हैदराबाद राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जिससे पूर्ण लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ (**Sarma, 2005**).

भाषाई पुनर्गठन और हैदराबाद का विभाजन (1956) : विलय के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act) था। हैदराबाद रियासत को भाषाई आधार पर तीन भागों में विभाजित कर दिया गया:

1. **तेलंगाना क्षेत्र:** आंध्र राज्य के साथ मिलकर **आंध्र प्रदेश** बना।
2. **मराठवाड़ा क्षेत्र:** इसे **बॉम्बे राज्य** (वर्तमान महाराष्ट्र) में मिलाया गया।
3. **कन्नड़ क्षेत्र:** इसे **मैसूर राज्य** (वर्तमान कर्नाटक) में शामिल किया गया।

परिणामों का संक्षिप्त तुलनात्मक चार्ट

क्षेत्र	विलय से पूर्व (Pre-1948)	विलय के पश्चात (Post-1948)
शासन प्रणाली	निरंकुश राजशाही (Autocracy)	संवैधानिक लोकतंत्र (Democracy)
अर्थव्यवस्था	जागीरदारी और सामंती व्यवस्था	भूमि सुधार और आधुनिक बैंकिंग

क्षेत्र	विलय से पूर्व (Pre-1948)	विलय के पश्चात (Post-1948)
सुरक्षा	रजाकारों का समानांतर शासन	भारतीय पुलिस और सेना का नियंत्रण
राजनीतिक स्थिति	स्वतंत्र रहने का प्रयास	भारतीय संघ का अभिन्न अंग

निष्कर्ष : हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता की पहली सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा थी। इस शोध के विस्तृत विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:

राष्ट्रीय अखंडता की अनिवार्यता : हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति भारत के हृदय स्थल में थी। यदि सरदार पटेल ने 'ऑपरेशन पोलो' का साहसिक निर्णय नहीं लिया होता, तो भारत के मानचित्र के बीचों-बीच एक संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण और स्वतंत्र राष्ट्र का अस्तित्व बना रहता। यह न केवल संचार और परिवहन के लिए बाधा होता, बल्कि भविष्य में भारत के 'बाल्कनीकरण' (टुकड़ों में बंटने) का आधार भी बन सकता था (**Menon, 1956**)।

सामंतवाद पर लोकतंत्र की विजय : निजाम का शासन एक अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग और दमनकारी जागीरदारी प्रथा पर आधारित था। रजाकारों के हिंसक उदय ने इस शासन की नैतिक वैधता को समाप्त कर दिया था। भारत सरकार के हस्तक्षेप ने न केवल रियासत को मुक्त कराया, बल्कि 85% बहुसंख्यक आबादी को पहली बार लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की (**Guha, 2007**)।

सरदार पटेल की कूटनीतिक और सामरिक सफलता : इस पूरे घटनाक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल की 'लौह पुरुष' की भूमिका निर्विवाद है। उन्होंने अत्यंत धैर्य के साथ पहले कूटनीतिक विकल्पों (यथास्थिति समझौते) को मौका दिया और जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ी, तब बिना किसी हिचकिचाहट के सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि यह जटिल मुद्दा मात्र 108 घंटों (5 दिन) में सुलझ गया (**Pradhan, 2014**)।

ऐतिहासिक मूल्यांकन और वर्तमान प्रासंगिकता : यद्यपि विलय के दौरान कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा देखी गई (जैसा कि सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित है), लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसने दक्षिण भारत में स्थिरता और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 1956 के भाषाई पुनर्गठन ने इस ऐतिहासिक एकीकरण को और अधिक सुदृढ़ बनाया, जिससे आज के आधुनिक तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों का उदय हुआ।

हैदराबाद का विलय भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जो यह सिखाता है कि एक राष्ट्र की संप्रभुता और जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। यह घटना आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा और एकता के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण बनी हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Comprehensive Bibliography) :

1. **Ali, Y. J. (2010).** *The Hyderabad State: A Study in Political and Social Change.* Rawat Publications. (pp. 145-160).
2. **Austin, I. (2001).** *City of Hope: The Formation of Hyderabad Design.* Oxford University Press. (pp. 88-92).
3. **Benichou, L. S. (2000).** *From Autocracy to Integration: Political Developments in Hyderabad State (1938-1948).* Orient Blackswan. (pp. 210-235).
4. **Copland, I. (1997).** *The Princes of India in the Endgame of Empire, 1917-1947.* Cambridge University Press. (pp. 250-262).

5. **Government of India. (1948).** *White Paper on Hyderabad.* Ministry of States, New Delhi. (pp. 15-45).
6. **Guha, R. (2007).** *India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy.* HarperCollins. (pp. 52-65).
7. **Menon, V. P. (1956).** *The Story of the Integration of the Indian States.* Longmans, Green and Co. (pp. 317-389).
8. **Munshi, K. M. (1957).** *The End of an Era: Hyderabad Memories.* Bharatiya Vidya Bhavan. (pp. 112-148).
9. **Nanda, B. R. (1990).** *Sardar Vallabhbhai Patel: A Pictorial Biography.* Publications Division. (pp. 75-80).
10. **Noorani, A. G. (2014).** *The Destruction of Hyderabad.* Tulika Books. (pp. 211-240).
11. **Pavier, B. (1981).** *The Telangana Movement, 1944-1951.* Vikas Publishing House. (pp. 120-135).
12. **Pradhan, R. D. (2014).** *Sardar Patel and Indian Administration.* Concept Publishing Company. (pp. 190-210).
13. **Ramachandran, P. (2008).** *Operation Polo: The Police Action Against Hyderabad.* Manas Publications. (pp. 45-78).
14. **Rao, P. R. (1988).** *History of Modern Andhra.* Sterling Publishers. (pp. 160-175).
15. **Sarma, R. N. (2005).** *Integration of Princely States in India.* Deep & Deep Publications. (pp. 102-118).
16. **Sherwani, H. K. (1986).** *The History of the Qutb Shahi Dynasty.* Munshiram Manoharlal Publishers. (pp. 301-315).
17. **Smith, W. C. (1950).** Hyderabad: Muslim Tragedy. *The Middle East Journal,* 4(1), 27-51.
18. **Sundarayya, P. (1972).** *Telangana People's Struggle and Its Lessons.* Communist Party of India (Marxist). (pp. 180-220).
19. **Talbot, I., & Singh, G. (2009).** *The Partition of India.* Cambridge University Press. (pp. 144-158).
20. **Taylor, S. (2013).** The Fall of the Nizam. *Indian Historical Review*, 40(2), 221-235.
21. **Zubrzycki, J. (2006).** *The Last Nizam: The Rise and Fall of the World's Richest Man.* Pan Macmillan. (pp. 155-189).

•